बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 207 ● नई दिल्ली ● सोमवार 18 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

गागन नदी फिर उफान पर, लाखों की फसल हो चुकी बर्बाद; यूपी में बारिश से और बिगड़ेंगे हालात

मुरादाबाद।रामगंगा नदी का जल स्तर भले ही गिर रहा है लेकिन, गागन नदी लगातार खतरे से निशान से ऊपर बह रही है। रविवार को दोपहर बाद हुई वर्षा का पानी का काफी हिस्सा भी गागन नदी में ही जाता है। इससे भी गागन नदी के पानी पर असर पड़ेगा। इसी तरह से लगातार वर्षा होते रहने पर नदियों के जल स्तर पर असर पड़ने की पूर्ण संभावना है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी से बर्बाद होने वाली फसलों के नुकसान का अभी तक आंकलन नहीं हो सका है। कुंदरकी के गांव केवर खास में रविवार दोपहर को हुई मूसलाधार वर्षा में किसान अमर सिंह के घर की कच्ची छत भरभराकर धराशायी हो गई। हादसे में घर पर कार्य कर रही दिव्यांग पत्नी मलबे में दब गई जबकि घर में मौजूद युवती मोनिका ने भागकर जान बचाई। घटना के समय किसान व उसके पुत्र कपिल, बिट्टू, चिंटू घर से बाहर थे।

चुनाव आयोग के साहसी कदम पर टिका है कई पीढ़ियों का भविष्य: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए कहा है कि उनका एक सही और साहसिक क़दम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से यह अपील ऐसे समय में की है, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम जिले से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। कुछ दिनों पहले ही संसद के मानसून सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे को लेकर समूचे विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आयोग से अनुरोध करते हुए लिखा, "चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है। आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये न समझें कि वो अकेले हैं। सपा प्रमुख ने लिखा है कि जब चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उसका रक्षा कवच बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलनेवालों के साथ जनता और जन विश्वास स्वयं चलने लगता है। यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग का एक सही और साहसिक क़दम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। सबको अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए।

40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर, एनसीआर वालों को पीएम मोदी की सौगात

- UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन
- लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई हैं दोनों सड़क परियोजनाएं
- सिंघु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट मात्र 40 मिनट पहुंच सकेंगे, अभी लगता है 2 घंटे
- दिल्ली को जाममुक्त करने में मिलेगी मदद, बेहतर हो सकेगा यातायात संचालन

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 अगस्त) को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले इन दो हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लोकार्पण से लोगों की आवाजाही आसान होगी। लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दोनों सड़क परियोजनाओं से एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में यातायात संचालन बेहतर होगा। अब द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंघु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। पहले इस सफर में 2 घंटे का वक्त लगता था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, पीएम मोदी नेतृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूं कि आप दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है। जिनकी नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राय बराबर का भागीदार है। जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। आप वो ताकत हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है।

जम्मू-कश्मीर में फिर कुदरत का कहर, कठुआ में बादल फटने से 7 की मौत

कठुआ। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के बाद, अब कठुआ जिले में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। एक सुदूर गांव में बादल फटने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुई। इससे पहले, किश्तवाड़ में भी इसी तरह की घटना में 60 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, बादल फटने से गांव के कई घर मलबे और बाढ़ के पानी में दब गए। इस त्रासदी के कारण गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि, पुलिस और एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस घटना से नुकसान पहुंचा है। कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बागड़, चांगड़ा और दिलवान-हुतली गांवों में भी भूस्खलन हुआ है, लेकिन वहां किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र के ज्यादातर जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उझ नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कठुआ के कई इलाकों में बारिश के कारण हुए विनाशकारी भूस्खलन में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है।

लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे- तेजस्वी यादव

वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही- तेजस्वी

सासाराम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। सासाराम में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि "वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार देकर सभी लोगों को ताकत दिया, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग को आगे करके वोट का अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आपके (जनता) वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है।

तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी, यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है...बिहार में हम बेईमानी नहीं होने देंगे। राजद नेता ने दावा किया कि वह जिन वादों की घोषणा करते हैं, बिहार की नीतीश कुमार सरकार नकल करके वही घोषणाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में नकलची सरकार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमें मौका मिला तो हम बिहार में विकास करने वाली सरकार देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही यात्रा में कथित वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को उठाया जाएगा।

'भाजपा की साजिश एसआईआर कराने और बिहार के चुनाव भी चुराने की है - राहुल गांधी

बिहार।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के सासाराम से अपनी मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश में चुनाव चुराने का आरोप लगाया। सासाराम में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं इस मंच से आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में विधानसभा और और लोकसभा के चुनाव चुराए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की ताज़ा साज़िश बिहार में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बहाने यहां के चुनाव चुराने की है। राहुल ने दावा किया, हम उन्हें यह चुनाव नहीं चुराने देंगे। उन्होंने कहा कि अब पूरा

देश जान चुका है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है।

राहुल के मुताबिक, पहले लोगों को यह नहीं पता था कि वोट कैसे चुराए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इंडिया ब्लॉक देश में सही मायने में जाति जनगणना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, हम वोट चोरी पर रोक लगाएंगे और स्तूककी सचाई उजागर करेंगे। राहुल गांधी ने इस मौके पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लालू जी, डॉक्टर की सलाह के बावजूद यहां आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।

- "बिहार में वोट अधिकार यात्रा, लालू बोले-बीजेपी को उखाड़ फेंको
- "राहुल ने कहा- ये संविधान बचाने की लड़ाई; तेजस्वी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया

खड़गे ने मोदी को बताया खतरनाक

इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, वह बहुत खतरनाक आदमी है। जब तक आप उन्हें सत्ता से नहीं हटाएंगे, आपके वोट, अधिकार, आज़ादी और यहां तक कि संविधान भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

खड़गे का यह बयान मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। इस यात्रा का मकसद आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की ताकत दिखाना और जनता को संगठित करना है।

बर्लिन में लहराया तिरंगा, गूंजे भारत माता की जय-प्रवासी भारतीयों मे जोश

बर्लिन, जर्मनी। भारत की आज़ादी के गौरवमयी इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रवासी भारतीय समुदाय ने 15 अगस्त का पर्व भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया। विदेशी धरती पर मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का यह अद्भुत नज़ारा हर किसी के मन में देशभक्ति की लहर जगा रहा था।

इस आयोजन में भारत से आए मेहमानों के साथ-साथ बर्लिन में कार्यरत प्रवासी भारतीय और उनके परिवार बड़ी संख्या में शामिल हुए। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराया, पूरा वातावरण ÷भारत माता की जय÷ और ÷हिन्दुस्तान ज़िंदाबाद÷ के नारों से गूंज उठा। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के चेहरों पर गर्व और खुशी की चमक देखते ही बनती थी, मानो वे कुछ पलों के लिए भारत की मिट्टी पर लौट आए हों।

इस अवसर पर राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा– विदेश में आकर भी हमारा दिल भारत की धड़कनों से जुड़ा है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए। यह स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिली, इसके लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए।

हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल भारत का गौरव बढ़ाएं बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का दीप जलाए रखें।÷

उन्होंने यह भी जोड़ा कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, भारत की आत्मा हमारे दिल में बसती है, और यही भावना हमें विश्व के सामने गर्व से खड़ा करती है।

प्रवासी भारतीय पुलकित चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं और बच्चों को भारतीय संस्कृति की पहचान कराते हैं। सुनीता चतुर्वेदी ने भावुक होकर कहा कि विदेश में तिरंगे को लहराते देखना एक अद्भुत और गर्वपूर्ण अनुभव है, जो हमें याद दिलाता है कि हम भारतीय हैं और हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है।

ध्वजारोहण के बाद सभी ने मौन रखकर उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तत्पश्चात मंच से सभी प्रवासी भारतीयों ने हाथ उठाकर यह संकल्प लिया कि वे जहां भी रहें, भारत की प्रतिष्ठा, संस्कृति और एकता की रक्षा करेंगे।

इस आयोजन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे–गौरव कुमार, राहुल प्रियदर्शी, यश, जतिन डंडोना, प्रज्ञा, सुनीता डंडोना, सुदाम, मृत्युंजय, करुणेश कुलश्रेष्ठ, रेनू कुलश्रेष्ठ, राजकुमार डंडोना, अंकिता श्रीवास्तव, सुनीता यादव और सिया।

इन सभी ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर इसे सफल बनाया और सामूहिक गर्व की भावना को सशक्त किया।कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

तिरंगे की शान में खड़े होकर उपस्थित सभी लोगों की आंखें गर्व और भावुकता से नम हो गईं। यह आयोजन केवल स्वतंत्रता दिवस का उत्सव नहीं था, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय की एकता, भाईचारे और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण था। बर्लिन में बसे भारतीयों ने एक स्वर में संदेश दिया कि चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों, उनका दिल हमेशा भारत के साथ धड़कता है।

ट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक महामुलाकात -अलास्का में नहीं बनी बात

3 घंटे बैठक,कोई डील नहीं हुई,12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस- अब मिशन मास्को

वैश्विक स्तरपर मानव इतिहास में संवाद,चाहे वह व्यक्तिगत हो,राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय,सदैव सबसे स्थायी और प्रभावशाली समाधान साधनों में से एक रहा है। युद्ध, हिंसा और हिंसात्मक संघर्षों ने अक्सर विनाश और अपरिवर्तनीय क्षति लाई है, जबकि बातचीत ने सम्मान, समझ और स्थायी परिवर्तन संभव करनेमें केंद्रीय भूमिका निभाई है।वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात (15 अगस्त 2025,देर रात्रि अलास्का) इस दृष्टिकोण का एक नवीनतम और व्यापक रूप से चर्चित उदाहरण है। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह दर्शाने का प्रयास करूंगा कि संवाद के माध्यम से बड़े से बड़े संकटों और युद्धों को कैसे टाला जा सकता है,एक व्यापक, विवेचनात्मक और संदर्भ-पूर्ण विश्लेषण।संवाद सिर्फ शब्दों की अदला-बदली नहीं है;यह एक संरचित प्रक्रिया है जो समझ, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य मतभेदों को समझना,साझा दृष्टिकोण विकसित करना और पारस्परिक स्वीकार्य हल तक पहुंचना है। एक विद्वान के अनुसार,संवाद सिर्फ सूचना का आदान-प्रदान नहीं,यह साझा समझ और भरोसा पैदा करने के बारे में है।15 अगस्त, 2025 को देर रात्रि भारतीय समय अनुसार करीब 2 बजे ज्वाइंट बेसएलमेंडोर्फ-रिचर्डसन,अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, जिसको मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से कवर कर रहा था। दोनों नेताओं की यूक्रेन पर आक्रमण 2022 केबाद पहली आमने-सामने बातचीत हुई रूस के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसेशुरुआती कदमबताया, जिसे बाद में यूक्रेन के जेलेंस्की को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से संवर्धित किया जा सकता है।वहीं पुतिन के उद्देश्य गहरे और रणनीतिक रहे,उन्होंने कोई क्षेत्रीय समझौता नहीं छोड़ा, बल्कि नाटो से दूरी बनाए रखने और यूक्रेन को निर्बल करने की दिशा में सोचा वर्तमान में जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात चर्चा में है, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संवाद एक दोधारी तलवार है,यह युद्ध को टालने का आधार बन सकता है,लेकिन इसकी परिणति उद्देश्य, संरचना, निष्पक्षता और पक्षकारों की मंशा पर निर्भर करती है।संवाद, जब सही तरीकों से, सही समय और संरचना में होता है, तो यह शांति की ओर निर्णायक कदम हो सकता है। वर्तमान में ट्रंप-पुतिन मुलाकात एक संयोग नहीं, बल्कि एक अवसर हो सकती है,यदि इसे रणनीतिक रूप से और न्यायपूर्ण रूप से आगे ले जाया जाए।अन्यथा,यह केवल दिखावटी संवाद बनकर रह जाएगा, जो संभवत: संघर्ष को टालने की बजाय बढ़ा सकता है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक महामुलाकात-अलास्का में नहीं बनी बात-3 घंटे बैठक,कोई डील नहीं हुई,12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस-अब मिशन मास्को की संभावना। साथियों बात अगर हम ट्रंप प्रतिनिधि अलास्का में हुई हाई प्रोफाइल महामुलाकात के नतीजे को समझने की करें तो,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली,राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शुरुआती कदमबताया, जिसे बाद में यूक्रेन के जेलेंस्की को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से संवर्धित किया जा सकता है,वहीं पुतिन के उद्देश्य गहरे और रणनीतिक रहे,उन्होंने कोई क्षेत्रीय समझौता नहीं छोड़ा,बल्कि नाटो से दूरी बनाए रखने और यूक्रेन को निर्बल करने की दिशा में सोचा।यह वार्ता एक पारंपरिक एक-पर-एक (वन-ऑन-वन) से हटकर, तीन- पर-तीन (3-ऑन-3) प्रारूप में हुई, जिसमें ट्रंप के पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, और पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तथा सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल थेमीडिया में हुई दिखावे भरी शुरुआत बैठक से पहले, दोनों नेताओं का रेड कार्पेट पर हाथ मिलाना,कार से एक साथ जाना, और आगे की रणनीति पर सैन्य विमानों (जैसे बी-2 स्टील्थ बमवर्षक और एफ-22 फाइटर) द्वारा फ्लाई ओवर ने इस मुलाकात की प्रतीकात्मक महत्वपूर्णता को उजागर किया। इसके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। ट्रम्प ने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए। वहीं, पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है।उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए।व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया कि मीटिंग के बाद वाशिंगटन लौटते समय ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से लंबी बातचीत की हालांकि, जेलेंस्की ने ट्रम्प-पुतिन की मुलाकात पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। साथियों बात अगर हम ट्रंप पुतिन की अलास्का में भी बैठक को एक समरी के रूप में देखें तो, ट्रम्प-पुतिन प्रेस ब्रीफिंग की 5 अहम बातें(1) ट्रम्प-पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं। (2)12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। (3) ट्रम्प ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। (4) पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी। (5) पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रम्प राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की दिशा में हुई चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह बैठक एक पारंपरिक एक-पर-एक मुलाकात के बजाय तीन-पर -तीन प्रारूप में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे। शुरुआत में किए गए प्रतीकात्मक स्वागत,जैसे रेड कार्पेट, सैन्य फ्लाईओवर और एक ही कार से यात्रा,ने बैठक को वैभवपूर्ण बनाया। ट्रंप ने युद्धविराम की तीव्र इच्छा जताई और रूस को चेतावनी दी, जबकि पुतिन ने रूस की सुरक्षा आवश्यकताओं व क्षेत्रीय आशंकाओं की बात रखी। बैठक में पहली बार ट्रंप ने नाटो के बाहर सुरक्षा गारंटी देने की संभावना का संकेत दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर निर्णय की नीति पर विवाद पैदा हुआ। वार्ता के अंत में दोनों ने रचनात्मकता की बात की लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया, जिससे शांति की दिशा में अनिश्चितता बनी रही। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कियट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक महामुलाकात-अलास्का में नहीं बनी बात-3 घंटे बैठक,कोई डील नहीं हुई,12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस- अब मिशन मास्को,मानव इतिहास में संवाद,चाहे वह व्यक्तिगत,राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो,सदैव सबसे स्थायी और प्रभावशाली समाधान साधनों में से एक ट्रंपपुतिन की अलास्का महामुलाकात के हाई प्रोफाइल होने का अंदाजा होटल पर हवाई जहाज उड़ानों पर अस्थाई प्रतिबंध से लगाया जा सकता है।

सम्पादकीय...

परिवार में कलह बढ़ाने की बातें

देखिए, देखिए, यह तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। माना कि यह लाल किले से मोदी जी का बारहवां भाषण था। इस बारहवें भाषण में ही मोदी जी को आरएसएस की महानता की याद आयी। यानी 2014 में मोदी जी के नयी आजादी लाने के बाद भी, आरएसएस को न ज्यादा न कम, पूरे बारह साल इंतजार करना पड़ा कि लाल किले से मोदी जी उसकी तारीफें करें, उसका गुणगान करें। उसकी देशभक्ति का बखान करें। अपने स्वयंसेवक होने का लाल किले पर चढ़कर एलान करें। जी हां! बारह साल लंबा इंतजार। उतना इंतजार, जितने इंतजार के बाद घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। लेकिन, सिर्फ इंतजार के साल बारह होने से ही, यह अर्थ कोई कैसे निकाल सकता है कि मोदी जी की नजर में आरएसएस कोई घूरा है। और यह अर्थ तो हर्गिज नहीं निकाल सकते हैं कि मोदी जी ने आरएसएस के साथ घूरे वाला सलूक किया है। अपने राज में आरएसएस के दिन तब तक नहीं फिरने दिए, जब तक कि उनके घूरे तक के दिन नहीं फिर गए। जब सब के दिन फिर चुके--अडानी जी के, अंबानी जी के, हिंदुजा जी, टाटा जी वगैरह, वगैरह के; उसके बाद ही कहीं जाकर आरएसएस के दिन फिरने दिए। ये सब संघ के परिवार में झगड़ा लगाने की बातें हैं। परिवार में कलह बढ़ाने की बातें हैं। क्या है कि बेचारों के परिवार में सब कुछ पहले ही ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर-ऊपर से तो सब ठीक नजर आता है, पर भीतर-भीतर काफी खींच-तान है। बाकी तो छोड़िए, भगवा पार्टी के अध्यक्ष के सलेक्शन पर झगड़ा शुरू हो गया तो समेटे में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीब डेढ़ साल होने आए, नड्डा जी को एक्सटेंशन पर ही गुजारा करते। न गद्दी पर कोई दूसरा आता है और न पक्का दूसरा कार्यकाल मिलता है। ऐसे में मोदी जी ने जरूर अपनी तरफ से नागपुरिया आकाओं को खुश करने की कोशिश की है। माना कि खास मोदी स्टाइल में खुश करने की कोशिश की है-दे न बांट की भुसी, बातों से ही कर दे खुशी; पर खुश करने की कोशिश तो की है। विरोधी इसे घूरे के बारह साल से जोड़कर, नाहक बात और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात भी समझने वाली है कि मोदी जी ने सिर्फ लाल किले से आरएसएस की तारीफ भर नहीं की है। मोदी जी की सरकार के पेट्रोलियम तथा गैस मंत्रालय ने बाकायदा एक पोस्टर जारी कर, सावरकर को गांधी, सुभाष, भगत सिंह, तीनों से ऊपर और तिरंगे से भी ऊपर बैठाने की जुगत भी भिड़ाई है। और असली बात यह कि यह तो इब्तदा -ए-इश्क है; आगे-आगे देखिए होता है क्या? सावरकर पर गांधी की हत्या के षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया था। उस सावरकर को अगर बारह साल होने पर सबसे ऊपर, गांधी से भी ऊपर बैठाया जा सकता है, तो कल को उस गोडसे को मोदी सरकार के पोस्टरों में आने से कौन रोक सकता है, जिसने गांधी का 'वध' कर के फांसी के फंदे को चूमा था। फिर यह तो शुरुआत है। प्लीज अब कोई ये मत कहने लगना कि सरकारी पोस्टर में सावरकर के सबसे ऊपर आने से ही क्या होता है? असली मुद्दा तो यह है कि गोलवलकर जी ऐसे पोस्टरों में कब आएंगे! आएंगे, गोलवलकर जी भी आएंगे। हेडगेवार जी भी आएंगे। भागवत जी भी आएंगे। सारे के सारे जी लोग ही आएंगे। जल्द ही आएंगे। बाकी सब को हटाएंगे, बस 'जी' लोग ही रह जाएंगे। बस थोड़ा धीरज चाहिए। सब होगा, बस मोदी राज को जरा सा टैम और मिल जाए। बस संघ पिचहत्तर साल की उम्र में मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की संगत में बैठने की जिद न पकड़ कर बैठ जाए। सच पूछिए तो मोदी जी को लाल किले से आरएसएस पर गर्व करने में, बारह साल इसीलिए लग गए कि वह पक्का काम करना चाहते थे। कहते हैं, सहज पके सो मीठा। संघ के लिए एक नया इतिहास पक कर तैयार होने के लिए, बारह साल इतने ज्यादा भी तो नहीं हैं। आखिर, आरएसएस को राष्ट्रद्रोही से, राष्ट्रवादी साबित करना था। उसने जिस आजादी की लड़ाई के खिलाफ काम किया, उसका अगुआ बनाना था। उसके सिर पर जिन अंग्रेजों ने हमेशा अपना हाथ रखा, उसे उनका पक्का विरोधी साबित करना था। आजादी की लड़ाई में उनकी हिस्सेदारी की लकीर, जो कहीं थी ही नहीं, उसे सबसे लंबा करना था। मुगलों-तुगलों को ही नहीं, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगतसिंह, सब को उनके ऊंचे आसनों से नीचे उतारना था। कांग्रेस को देश के विभाजन का दोषी और आरएसएस को देश की एकता झंडाबरदार साबित करना था। सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद साबित करना था। सांप्रदायिकता के लिए आजादी के बाद तीन-तीन बार लगी पाबंदियों को, आरएसएस के साथ हिंदू-विरोधियों का अन्याय साबित करना था। जाहिर है कि यह काम जल्दी में नहीं हो सकता था। यह काम जल्दी में अच्छा और पक्का नहीं हो सकता था। मोदी जी ने जरूर बारह साल लंबा रास्ता लिया, पर काम पक्का किया। एनसीईआरटी का स्कूली बच्चों के लिए नया पाठ है- विभाजन के तीन दोषी-जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। इस सिलसिले में आरएसएस का जिक्र सिलेबस के बाहर है। और मोदी जी ने सिर्फ जुबानी जमा-खर्च थोड़े ही किया है। उन्होंने सिर्फ आरएसएस की तारीफ करके ही नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने आरएसएस के एजेंडा को जोर-शोर से आगे बढ़ाने का एलान भी तो किया है। सुना नहीं कैसे उन्होंने पहली बार लाल किले से एलान किया कि आबादी के बदलाव से हिंदू खतरे में पड़ रहा है। परायों की घुसपैठ से देश के लिए खतरा बढ़ रहा है। सीमावर्ती इलाकों में ऐसी घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए, तो बिहार मार्का एसआईआर जरूरी है, अकेले बिहार में ही नहीं, देश भर में। पहले, घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे, फिर समाज और देश से। नहीं तो, लव जेहाद से बहन-बेटियों पर खतरा आ जाएगा बल्कि आ गया है। वे जमीन जिहाद कर के हमारे लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। रोटी-रोजगार जिहाद कर के नौजवानों के रोटी-रोजगार को हड़प कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। पर पता नहीं हिंदुओं के कैसे दिन फिर रहे हैं कि मोदी जी जैसे-जैसे खुले मैदान में उतरकर हिंदुओं को बचाने के लिए तलवार चलाते हैं, वैसे-वैसे हिंदू ज्यादा खतरे में आते जाते हैं। कौन जाने ज्यादा खतरे में आना भी दिन फिरना हो। कम से कम मोदी परिवार के दिन फिरना तो जरूर है।

मतदाता की महत्ता का प्रश्न

भारत में नागरिकों को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें मौलिक या मूलभूत अधिकारों के अलावा संवैधानिक अधिकार भी शामिल हैं। संवैधानिक अधिकारों में सम्पत्ति का अधिकार और वोट देने का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिकार का प्रयोग करके भारत का मतदाता सत्ता में सीधे अपनी भागीदारी अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की मार्फत करता है। भारत के लोकतन्त्र का मूलाधार यही वोट का अधिकार है। हकीकत यह है कि इस वोट के अधिकार की बात आजादी के आन्दोलन के दौरान ही जमकर होने लगी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के प्रत्येक वयस्क मतदाता को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जाये। 1931 में कराची में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ। मगर इससे भी पहले 1928 में श्री मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत का संविधान लिखने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में भारत के सभी वर्गों व व्यवसायों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया मगर जिन्ना को मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। इस समिति में पं. जवाहर लाल नेहरू व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भी शामिल थे। समिति ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की उसमें देश के सभी वर्गों, जातियों, व्यवसायियों व सम्प्रदायों के वयस्कों को एक वोट का अधिकार देने की सिफारिश की गई। इससे पहले अंग्रेजों ने केवल चुनिन्दा लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया हुआ था। इसमें उच्च शिक्षित व जमींदार तबके के लोग ही शामिल थे। यह वोट प्रतिशत दो से तीन प्रतिशत के करीब ही था जिसे 1935 में बढ़ा कर 11 प्रतिशत के करीब किया गया था। मगर मोती लाल समिति ने सर्वसम्मति से इसे 100 प्रतिशत वयस्क आधार पर देने की सिफारिश की। वास्तव में इस समिति ने भारत के संविधान का मोटा प्रारूप तैयार कर लिया था। इसमें केन्द्र व राज्यों के सम्बन्ध व भाषा जैसे विषय भी शामिल थे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार भी इस समिति ने तय कर दिये थे। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उन्हीं की अध्यक्षता में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया था। भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के प्रस्ताव के साथ ही नागरिकों को सत्ता के विरुद्ध मौलिक अधिकार देने का वचन इस अधिवेशन में दिया गया था। मगर मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान यह किया गया था कि उनके घरेलू मामलों के नियमों में सत्ता किसी प्रकार का दखल नहीं देगी। इसकी वजह यह थी कि 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से राज्य बनाने की मांग की गई थी। इस लीग अधिवेशन की सदारत प्रख्यात शायर अल्लामा इकबाल ने की थी। उनकी सदारत में ही लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य या देश बनाने की मांग की थी। कांग्रेस को तब मुहम्मद अली जिन्ना हिन्दू पार्टी बताता था और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को इसका पिट्ठू या दिखावे का व्यक्ति (शो ब्वाय) बताता था। अतः कांग्रेस ने मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष छूट दी थी। परन्तु धर्म के आधार पर ही जब हिन्दुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया तो उन्हें दी गई विशेष छूट को तुष्टिकरण कहा गया। उस समय तक संविधान बनाने की प्रक्रिया बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रही थी। अतः बाबा साहेब ने संविधान लिखते हुए मोती लाल नेहरू समिति की सिफारिशों को केन्द्र में रखा और स्वतन्त्र भारत में प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को एक वोट का अधिकार दिया। मोती लाल नेहरू समिति ने इसकी अनुशंसा अपनी रिपोर्ट में पहले ही कर दी थी। यह इतिहास लिखने की जरूरत इस लिए पड़ी जिससे देश की नई पीढ़ी के लोग यह जान सकें कि उन्हें मिला एक वोट का अधिकार कितने संघर्षों व प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद मिला है। अतः चुनाव आयोग बिहार में यदि 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर कर देता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में हो रहे सघन मतदाता पुनरीक्षण का मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इतनी बड़ी संख्या में काटे गये मतदाताओं के नामों की वजह बताये तथा जिन मतदाताओं के नाम काटे गये हैं उनके नामों की सूची जारी करे और उन्हें अच्छी तरह प्रचारित व प्रसारित करे। प्रत्येक ब्लाक (प्रखंड) स्तर पर लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसका नाम किस वजह से काटा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 2003 से लेकर अब तक लगभग 22 लाख मतदाता मर चुके हैं जिन्हें लेकर भारी विवाद हो रहा है। आयोग द्वारा घोषित मृत लोगों में से कुछ जीवित पाये जा रहे हैं। इसी प्रकार आयोग ने कहा है कि 30 लाख से ऊपर मतदाता बिहार छोड़ कर अन्यत्र जा चुके हैं और वहीं बस गये हैं। पहले चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में ही यह कहा था कि काटे गये मतदाता नामों की वजह बताना उसके लिए जरूरी नहीं है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित मानते हुए ही नये आदेश जारी किये। जाहिर है कि चुनाव आयोग ऊंची मसनद पर बैठकर इस प्रकार की दलील नहीं दे सकता क्योंकि उसका मुख्य कार्य मतदाताओं को जोड़ने का है। बेशक बिहार में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी पिछले 28-30 सालों में मृत्यु हो चुकी होगी और लाखों लोग अन्य राज्यों को पलायन भी कर गये होंगे मगर उनके नाम की सूची न जारी करने का आयोग का फैसला पूरी तरह इकतरफा व मनमाना था जबकि चुनाव आयोग ही भारत के मतदाताओं का संरक्षक है और त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाना उसका परम कर्तव्य है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सूची प्रकाशन का आदेश जारी कर भारत के लोकतन्त्र को मजबूत किया है और इसमें आम आदमी की भागीदारी को प्रथम कर्तव्य माना है।

हरेक के लिए सहज हो हैल्थ सेवा

हाल के वर्षों में भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निजी इक्विटी (पीई) फर्मों के लिए एक आकर्षक निवेश क्षेत्र बन गया है। 2022-24 के बीच भारतीय अस्पतालों में कुल 6.74 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, जिसमें पीई निवेशकों ने 4.96 बिलियन डॉलर का निवेश शामिल था। इस निवेश के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उद्देश्य होना था। हालांकि, पीई फर्मों द्वारा, भारत की विशाल आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अस्पतालों के अधिग्रहण में उनके सामान्य पूंजी निवेश और समयबद्ध लाभ कमाने के उद्देश्य के अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों और सार्वजनिक सेवा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह एक ऐसी सेवा है जो समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के अधिकांश अस्पताल सामाजिक सेवा में जुटे हुए संस्थानों, ट्रस्टों और कई प्रसिद्ध और सफल डॉक्टरों द्वारा समाज में सेवा भाव से स्थापित किए गये थे, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बढ़ती हुई आबादी और नई बीमारियों से संबंधित पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि शहरी-ग्रामीण असमानतायें जहां 60फीसदी अस्पताल बिस्तर महानगरों में केंद्रित है, जबकि 70फीसदी आबादी गैर-महानगरीय क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट, इलाज और दवाईयों के बढ़ते हुए निजी खर्च और अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे ने कई लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच से बाहर कर दिया है। ऐसे में पीई फर्मों का निवेश इन कमियों को दूर करने का एक अवसर हो सकता है, बशर्ते यह लाभ के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राथमिकता दे। पीई फर्मों का निवेश और व्यवसाय मॉडल सामान्यतः आमतौर पर तीन से सात साल की अवधि में अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। यह मॉडल आम निवेश के लिए तो ठीक है लेकिन अस्पतालों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यह लागत में कटौती, अनावश्यक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और उच्च लाभ वाली विशेषज्ञताओं जैसे (जैसे ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी) पर ध्यान केंद्रित करने का दबाव डाल सकता है और मरीजों की स्थिति को अनदेखा कर सकता है। अमेरिका में पीई के स्वामित्व वाले अस्पतालों से संबंधित एक स्टडी में देखा गया है कि प्राथमिक देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं की उपेक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता में कमी और लागत में वृद्धि हुई। देखा गया है कि भारत में कुछ पूंजी निवेश जो स्वास्थ्य क्षेत्र के तजुर्बेकार निवेशकों जैसे आईएचएच द्वारा फोर्टिस में किया गया था, उनमें इन बातों का ध्यान रखा गया था। पूंजी निवेश के समय निवेशक की बैकग्राउण्ड और पिछले तजुर्बे का ध्यान रखना भी आवश्यक है। 1. सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाः पीई निवेश का उपयोग ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों और क्लीनिकों का विस्तार करने के लिए किया जाना चाहिए। इस निवेश में, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, यह आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर सस्ती स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने पर भी जोर देना चाहिए, जो देश के अधिकांश लोगों को कवर करती है।

पीएम मोदी का भाषण: लाल क़िले के प्राचीर से 2014 की यादें

सुनील कुमार

79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कई बार 2014 की चुनावी रैलियों की याद दिला गया। प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं, जो उनके भाषण के वाक्यों से ली गई है और जिन पर हमारी टिप्पणी है। प्रधानमंत्री कहते हैं– स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा है, गर्व से भरा जा रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स अब सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप्स में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। हाँ मोदी जी, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा है, और मीडिया हमें गर्व से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या यह विडम्बना नहीं है कि हम चाँद और मंगल पर झंडा गाड़ने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन धरती पर लाखों लोग इलाज के बिना मर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में एक बेड पर तीन-तीन मरीज पड़े हैं। बच्चे जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और कुछ तो वहीं जान भी गंवा रहे हैं। आप जिस समय लाल किले के प्राचीर से संबोधन कर रहे थे, उसी समय उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा में निर्माणाधीन पीएम-श्री स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गई। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे बूंदी में फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। दिल्ली जैसे शहरों तक में पीने का साफ पानी नहीं है। गाँव की औरतें आज भी पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलती हैं। अंतरिक्ष में 'आत्मनिर्भरता' का सपना जितना सुनहरा है, धरती पर आत्मनिर्भर नागरिकों के लिए बुनियादी ढाँचा उतना ही खस्ताहाल है। विकास की असली पहचान आसमान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आम आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। वरना, चाँद पर तिरंगा लहराने से पहले हमें धरती पर इंसानों की गरिमा बहाल करनी होगी। हम एक तरफ मंगल पर जाने का सपना बुन रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जनता रसातल में जा रही है। अगर यही विकास है, तो फिर गरीब जनता को भी बता दीजिए–दवाई के लिए अस्पताल, स्कूल मत जाओ, चाँद की तरफ देखो। धरती अब सिर्फ बड़े-बड़े सपनों और टीवी कैमरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या वोकल फॉर लोकल का नारा देते आए हैं और कहते हैं कि इस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। प्रधानमंत्री जी की कार से लेकर घड़ी, चश्मा, पेन सब विदेशी है। यहाँ तक कहा जाता है कि खाने में आप विदेशी मशरूम इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं– जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है, तो देशवासियों को लाभ मिलता है 75 साल आज़ादी के ऐसे ही गए, हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया और न्याय संहिता को ले आए हैं। हाँ, लेकिन आपने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड लाने की तैयारी की है, जिससे मजदूरों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा। आप तीन कृषि कानून लाए, जिनका पूरे देश के किसान संगठनों ने विरोध किया और 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी। बिजली कानून लाकर धन्ना सेठों की जेब भरना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। आपके तथाकथित 'सुधार' जनता के शोषण के लिए हैं और अपने दोस्त उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के लिए। कोरोना काल में देखा गया, 2020 में भारत में करीब 4.6 करोड़ लोग गरीबी में धंस गए। इसी अवधि में भारत में अमीरों की संख्या करीब 40 फीसदी बढ़कर 102 से 143 हो गई। अडानी समूह की संपत्ति 27.4 अरब डॉलर बढ़कर 61.2 अरब डॉलर हो गई, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति 2.61 अरब डॉलर बढ़कर 79.3 अरब डॉलर हो गई। प्रधानमंत्री कहते हैं– ऐसे-ऐसे कानून हैं हमारे देश में, छोटी-छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून हैं... उन्हें खत्म होना चाहिए। मोदी जी क्या इन कानूनों से भीमा कोरेगांव जैसे मामलों में जेल में बंद लोगों को राहत मिलेगी? जिन्हें बिना ट्रायल 7 वर्षों से अधिक समय से जेल में रखा गया है। जमानत मिलने के बाद भी घर जाने की इजाजत नहीं मिली है। या इन कानूनों से राम रहीम जैसे बलात्कारियों और 'सहारा श्री' जैसे भ्रष्टाचारियों को लाभ होगा ? प्रधानमंत्री कहते हैं– इस दिवाली मैं आपके लिए डबल दिवाली का काम करने वाला हूं... पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा सुधार किया, पूरे देश में टैक्स का बोझ कम किया। मोदी जी, जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई का भार और बढ़ा। आपने कहा था कि 15 तरह के टैक्स हटाकर एक टैक्स–जीएसटी–लागू होगा। लेकिन आपके नेतृत्व में 15 टैक्स को ही वस्तु मूल्य मानकर उसके ऊपर जीएसटी जोड़ दिया गया, जिसके बाद पूंजीपतियों के खजाने रॉकेट की गति से भरने लगे। जीएसटी के नाम पर आपने राज्यों पर नियंत्रण और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं–आज देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और जल्द ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। 2023-24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपये से अधिक है। पर हकीकत यह है कि आज भी 6-7 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर महिलाएं 8-10 घंटे काम कर रही हैं। 24 जुलाई, 2025 को दिल्ली के रिठाला में फैक्ट्री में आग लगने से दो महिलाओं की जलकर मृत्यु हो गई। वे मात्र 7 और 7.5 हज़ार रुपये महीना वेतन पर काम करती थीं। भारत चौथी से तीसरी या पहली अर्थव्यवस्था बन भी जाए, तो क्या ऐसे परिवारों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा? प्रधानमंत्री घोषणा की–मेरे देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना आज से शुरू हो रही है–प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवक-युवतियों को 15 हज़ार रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपके 15 हज़ार रुपये देने से उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 18,400 रुपये (हेल्पर) से 22,400 रुपये (कारीगर) है, लेकिन उन्हें 8-12 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। यानी सालाना 1-1.5 लाख रुपये की लूट इनसे की जाती है। यह सब आपके नाक के नीचे हो रहा है। हो सकता है इनमें से कई फैक्ट्री आपके सांसदों या विधायकों या उनके रिश्तेदारों की हों। आप उनको उचित मजदूरी दिलाने के बजाय 12 घंटे कार्यदिवस का कानून लाने जा रहे हैं। यह सुनकर 2014 का आपका वादा याद आता है, जब आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपके शासनकाल में बेरोजगारी से आत्महत्या करने वालों की संख्या चौंकाने वाली है–2018 में 2,741, 2019 में 2,851 और 2020 में 3,548 हो गई। यह आंकड़ा 2021 में कोरोना काल के बाद, 11,724 हो गया।

प्रधानमंत्री कहते हैं– आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मान रहा है... स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक, खेल के मैदान से लेकर सेना तक, बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों को यौन शोषण के खिलाफ धरना देना पड़ा, और जब वे नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन मार्च करना चाहती थीं, तो पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें कैसे घसीटा और धरना स्थल हटा दिया। आप तब चुप रहे और आज लाल किले से नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। APDR की रिपोर्ट के अनुसार, 16 मौजूदा सांसद और 135 विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपी हैं, जिनमें 5 सांसद आपकी पार्टी के हैं। NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के साथ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज हुए, जिनमें बलात्कार के 31,516 मामले हैं। यह अनायास ही आपके 2014 के नारे–बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार–की याद दिलाता है। आप किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन आपके नीतियों के कारण भारत में दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हुआ, जिसमें 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी। आज भी किसानों की मुख्य मांग–फसलों का लाभकारी मूल्य–अधूरी है। किसानों को खाद लेने के लिए भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। यह सब सुनकर 2014 के आपके नारे–मेरे देश का किसान, देश की शान और अधिक उत्पादन, अधिक आमदनी–याद आ जाते हैं। न्यूजलान्ड्री की एक रिपोर्ट बताती है–जहां नरेंद्र मोदी ने किसानों से चाय पर चर्चा की थी, वहां किसानों की आत्महत्या दोगुनी हो गई। प्रधानमंत्री कहते हैं– गरीबी क्या होती है, यह मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा। मैं जानता हूं, सरकार में भी रहा हूं और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार केवल फाइलों में न हो, बल्कि देश के नागरिकों के जीवन में हो... हम उसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी, यदि आप वास्तव में गरीबी को जानते हैं तो मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना क्यों लगाते? क्या आप नहीं समझते कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर गरीबों के खातों से 2014-15 से 2023-24 के बीच 15,519 करोड़ रुपये (जिसमें प्राइवेट बैंक शामिल नहीं हैं) सार्वजनिक बैंकों ने वसूले हैं? वहीं, बैंकों से कर्ज लेकर मस्ती करने वालों के 10 वित्तीय वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये के एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया गया। महोदय, आपका यह गरीबी जानना गरीबों की जान लेने जैसा है। यह आपके 2014 के स्लोगन–अच्छे दिन आने वाले हैं–की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं–आज 10 करोड़ गरीब और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नया मिडिल क्लास तैयार हुआ है। महोदय, वित्त मंत्री बताती हैं कि जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं।

जनधन योजना गरीबों के लिए थी और 140 करोड़ की आबादी में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में से 55 करोड़ के जनधन खाते हैं–आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि गरीबी घटी है या बढ़ी है। आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करते हैं। आपके ही आंकड़ों के अनुसार, देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। तो क्या आप मिडिल क्लास को भी मुफ्त राशन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं–आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 वर्षों की राष्ट्रसेवा, सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन इसकी पहचान है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

पीएम मोदी की रैली को लेकर आप का बड़ा दावा, सौरभ भारद्वाज बोले- जबरदस्ती लाए गए सफाईकर्मी

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की रैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास रैली में जुटाने के लिए जनता और कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए सफाईकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों को जबरन बुला कर रैली में ले जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा मानो दिल्ली में लंबे समय बाद बीजेपी की सरकार बन गई है और लोग उमड़ कर उनकी रैली में पहुंचेंगे। लेकिन हालात उनकी सोच से परे नजर आ रहे हैं। भारद्वाज के अनुसार, दिल्ली की जनता उनकी रैली में जाने को तैयार नहीं है, इसलिए नगर निगम सफाई कर्मी, मलेरिया कर्मचारी और शिक्षकों को जबरन ले जा रहा है।

जन्माष्टमी के बाद रात भर जागे कर्मचारी, सुबह बुलाए गए रैली में

उन्होंने कहा, कल जन्माष्टमी थी। पूजा के बाद लोग देर रात घर लौटे और सफाई कर्मचारी भी लगभग रात 2 बजे से पहले नहीं सो पाए, बावजूद इसके, आज सुबह 7 बजे उनकी अटेंडेंस ली गई और उन्हें धमकाकर उन्हें मालवीय नगर के बाबा का ढाबा पहुंचने का आदेश दिया गया। आप प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि, उनकी पार्टी के कुछ पार्षद सुबह 7-8 बजे कई पॉइंट्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि, गरीब कर्मचारियों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि, बीजेपी के पास पीएम की रैली में लाने के लिए अपने लोग और कार्यकर्ता नहीं बचे, इसलिए कर्मचारियों पर रैली में जाने के लिए दबाव डाला गया।

दलित सफाईकर्मियों को मजबूर करना शर्मनाक

आप नेता ने बीजेपी पर दलित सफाईकर्मियों को जबरन रैली में ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह न सिर्फ तानाशाही है, बल्कि बीजेपी के लिए शर्म की बात भी है। उन्होंने दावा किया कि सेंट्रल जोन के डीसी ने आदेश जारी कर 16 अगस्त की छुट्टी के दिन सभी विभागों को रैली में कर्मचारियों को भेजने का फरमान सुनाया।

हमारे पास 70 वीडियो सबूत- भारद्वाज

भारद्वाज ने कहा कि कल तक बीजेपी को भरोसा था कि, उनके कार्यकर्ता और जनता रैली स्थल पर बसें भर देंगे। लेकिन जब उन्हें अंदेशा हुआ कि भीड़ नहीं जुट पाएगी और यह बड़ी बेइज्जती होगी, तब आनन-फानन में ऑर्डर निकालकर कर्मचारियों को बुलाया गया। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस जबरन भीड़ जुटाने के उनके पास पक्के सबूत हैं। उन्होंने बताया कि, उनके पास दिल्ली के 70 अलग-अलग स्थानों से ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जहां कर्मचारियों को दबाव डालकर पीएम की रैली में भेजा गया।

चुनाव जीते वोट चोरी और तोहफे बांटकर

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, बीजेपी ने यह चुनाव वोटर-लिस्ट में हेराफेरी करके, कहीं साड़ी, कहीं जूते और कैश बांटकर जीता। असली लोगों के वोट काटे गए और धोखाधड़ी से सरकार बनाई गई, इसलिए लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं।

बीजेपी पर आप ने कसा तंज

दिल्ली के हालात बिगड़ रहे हैं। आए दिन नाले में गिरने, बिजली के खंभे या पेड़ गिरने जैसी घटनाओं में लोग जान गंवा रहे हैं। जबकि, बीजेपी की सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, गरीब आदमी इनके साथ नहीं है, लोग आज आवारा कुत्तों के लिए तो इकट्ठा हो जाते हैं, मगर इनकी रैली में जाने को तैयार नहीं।

रामलीला मैदान में पशुप्रेमियों का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर आदेश का विरोध, लगाए नारे- आवारा नहीं हमारा है

नई दिल्ली। रामलीला मैदान के बाहर रविवार को पशुप्रेमियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस बीच वे आवारा नहीं हमारा है जैसे नारे लगाते रहे। वे सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को एकत्र कर आश्रयस्थलों में रखने वाले आदेश का पुरजोर विरोध करने के लिए यहां एकजुट हुए थे। इस बीच वे बड़े ही आक्रोशित दिखे। उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय को पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला कहा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी आदेश को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई इसे दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों में होने वाले शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए सही कह रहे हैं तो पशुप्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद से दिल्ली की सड़कों पर पशु प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शनों के चलते इन पर मुकदमा दर्ज भी हो रहा है। हालांकि, रविवार को हो रहे इस प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की मंजूरी है। रामलीला मैदान के बाहर जब पर्याप्त संख्या में पशुप्रेमी एकत्र हो गए तो उन्होंने मार्च निकाला, जो कमला मार्केट होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए रवाना हुआ। इस बीच ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। राह चलते राहगीरों को उमस का सामना करना पड़ा।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली । रविवार दोपहर को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। जहां एक तरफ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं, दूसरी तरफ कई इलाकों में जलभराव हो गया। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली एसनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने रविवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 व 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा अनुमान जताया था। बता दें कि शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में 0.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। आया नगर में 4.6, रिज में 1.8, लोधी रोड में 0.2 और पालम में बारिश दर्ज की गई।

नेहरू प्लेस में फाइव स्टार होटल से 10,000 करोड़ कमाएगा डीडीए, एलजी सक्सेना की देखरेख में नई योजना शुरू

नई दिल्ली। नेहरू प्लेस में डीडीए की 2 एकड़ जमीन फाइव स्टार होटल बनाने का ठेका फ्लूर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इस प्रोजेक्ट से 55 साल में डीडीए को करीब 10,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा 500 कमरों वाला होटल होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की देखरेख में डीडीए ने पुराने फ्रीहोल्ड और स्थायी लीज मॉडल को बजाय नई लाइसेंस संपत्ति योजना शुरू की है। इसका मकसद दिल्ली को कीमती जमीन को होटल, वेयरहाउस, स्वास्थ्य और बड़े रिटेल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इसमें पहला प्रोजेक्ट नेहरू प्लेस में 2 एकड़ जमीन पर फाइव स्टार होटल का है। इस साल 2 मई को इसके लिए निविदा जारी हुई थी। 13 अगस्त को नीलामी में फ्लूर होटल्स ने 27.19 करोड़ रुपये सालाना लाइसेंस फीस की बोली लगाकर ठेका जीता। ये राशि तय न्यूनतम फीस 18 करोड़ से 50 फीसदी ज्यादा है। इस फीस में हर साल बढ़ोतरी होगी जिससे 55 साल में डीडीए को करीब 10,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। फ्लूर होटल्स, लेमन ट्री होटल्स की सहायक कंपनी है। ये औरिका-नेहरू प्लेस नाम से 500 से ज्यादा कमरों वाला दिल्ली का सबसे बड़ा होटल बनाएगी। ये होटल शानदार कमरे, बेहतरीन डाइनिंग, बड़े बैंक्वेट हॉल और आधुनिक सुविधाओं के साथ बिजनेस व पर्यटन यात्रियों को आकर्षित करेगा। लेमन ट्री होटल्स के चेयरमैन पतंजलि केसवानी ने कहा कि दिल्ली उनके लिए खास है। औरिका-नेहरू प्लेस स्टाइल, आराम और शानदार सेवा का प्रतीक होगा। इस योजना से डीडीए को भारी राजस्व मिलेगा। होटल प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

वजीराबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का काम अटका, नहीं मिली हरे पेड़ों को हटाने की अनुमति

नई दिल्ली । भजनपुरा और यमुना विहार के बीच बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का काम पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने से अटक गया है। यह फ्लाईओवर दिल्ली मेट्रो के मौजपुर से मजलिस पार्क कॉरिडोर का हिस्सा है जिसमें ऊपरी डेक पर मेट्रो व निचले डेक पर चार लेन का फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर के दोनों उतरने वाले हिस्सों (भजनपुरा और बृजपुरी) में करीब 80 से अधिक हरे पेड़ आ रहे हैं। मेट्रो ने कॉरिडोर के लिए वायाडक्ट का निर्माण पूरा कर लिया है लेकिन सड़क को फ्लाईओवर से जोड़ने वाले दोनों तरफ के रैंप पेड़ों की वजह से अभी तक नहीं बन सके हैं। यह दिल्ली का पहला डबल-डेकर वायाडक्ट है जिसके निचले डेक में चार लेन की सड़क होगी। भजनपुरा और यमुना विहार के बीच यह खंड करीब 1.4 किलोमीटर लंबा है। कुछ महीनों से काम रुके होने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने हाल ही में निर्माण कार्य की समीक्षा की थी और विभाग को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था। परियोजना का निर्माण डीएमआरसी कर रही है जबकि धनराशि दिल्ली सरकार दे रही है। इसका रखरखाव पीडब्ल्यूडी करेगा। दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत बन रहे तीन डबल-डेकर वायाडक्ट में से यह पहला है। इसकी घोषणा 2021 में की गई थी। तीनों में से सबसे लंबा 2.4 किलोमीटर का वायाडक्ट संगम विहार और आंबेडकर नगर स्टेशनों के बीच एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर पर होगा। दूसरा वायाडक्ट आजादपुर और रानी झांसी रोड चौराहे के बीच आरके आश्रम मार्ग-जनकपुरी पश्चिम कॉरिडोर पर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। मौजूदा समय में भजनपुरा और यमुना विहार के बीच बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। फ्लाईओवर बनने से भजनपुरा, यमुना विहार, मौजपुर व आसपास के लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। लंबी दूरी वाले वाहन सीधे फ्लाईओवर से गुजर सकेंगे जिससे स्थानीय यातायात पर दबाव कम होगा। खास बात यह भी है कि खजूरी चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रमुख ट्रैफिक बिंदु है। ये लंबे समय से भीड़ और जाम की समस्या से जूझ रहा है। फ्लाईओवर और मेट्रो परियोजना से खजूरी चौक पर जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। चार लेन का फ्लाईओवर खजूरी चौक के आसपास के यातायात को डायवर्ट करेगा, जिससे चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा।

कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करेगी सरकार; शुभांशु शुक्ला की भारत वापसी पर लोकसभा में होगी विशेष चर्चा

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह विधेयक जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करेगा। लोकसभा की वेबसाइट पर प्रकाशित लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, मंत्री जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए, विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने के लिए अपराधों को अपराधमुक्त बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करना है। इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। एक अधिकारी के अनुसार, इस कदम से देश में अधिक व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक देश के

व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले 2023 में, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटा दिया है। कुछ नियमों में कारावास को हटा दिया गया और जुर्माने को बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदल दिया गया। 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जो सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगें, लेकिन इनमें मामूली बातों पर कारावास का प्रावधान है, और किसी ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो भारतीय नागरिकों को सलाखों के पीछे डालते हैं, समाप्त किए जाएं। हमने पहले संसद में एक विधेयक पेश किया था, हम इसे इस बार फिर से लाए हैं। सरकार ने पहले 40,000 से ज्यादा गैरजरूरी अनुपालनों को समाप्त किया। साथ ही 1,500 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को भी रद्द किया गया। सरकार ने भारतीय अंतरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला की भारत वापसी के उपलक्ष्य में सोमवार को लोकसभा में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव भी रखा है।

मृतका के रोते दिखाई देने से नहीं बन सकता दहेज उत्पीड़न का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। दहेज हत्या और क्रूरता के एक मामले में पति और उसके परिवार के सदस्यों को बरी किए जाने के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल मृतका के रोते हुए दिखाई देने के आधार पर दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति नीना कृष्णा बंसल की पीठ ने कहा कि मृतका के भाई और बहन के बयानों से प्रथम दृष्टया यह भी साबित नहीं होता कि मृतका को उसके ससुराल वालों द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए परेशान किया जा रहा था । कोर्ट ने पाया कि मृतका की बहन अपने बयान में कहा था कि तीजों के अवसर पर उसने अपनी बहन को फोन किया था और उसे रोते हुए पाया था। कोर्ट ने कहा कि मृतका रो रही थी, इसलिए दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बन सकता। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने मृतका के पिता द्वारा दहेज हत्या और क्रूरता के अपराधों के लिए पति और उसके माता-पिता को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से उनकी बेटी को पर्याप्त दहेज न लाने के लिए लगातार अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। यह भी आरोप लगाया गया था कि मांगें पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि, आरोपितों को बेबुनियाद बताते हुए पीठ ने कहा कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु निमोनिया के कारण हुई थी और दहेज हत्या के अपराध से अभियुक्तों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से विचार किया था। पीठ ने कहा कि मृतका की मृत्यु किसी क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारणों से हुई थी। पीठ ने कहा कि पिता की तरफ से दहेज के रूप में पैसे देने के संबंध में कोई सुबूत नहीं पेश किया गया।

राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर भाजपा का तंज, कहा- यह झूठ की बुनियाद पर कहानी गढ़ने की कोशिश

नई दिल्ली ।बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता सीआर केसवन ने इसे संविधान बदनाम यात्रा करार दिया। वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की नींव कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यात्रा को पंक्चर टायर कहा। राहुल गांधी और कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा बिहार में 16 दिनों तक चलेगी और करीब 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भाजपा नेता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर अलोकतांत्रिक और छलपूर्ण तरीके से भय फैलाने की रणनीति के तहत संविधान खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी राजद एक व्यक्ति, एक वोट की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनका असली एजेंडा एक परिवार और एक वंशवादी शासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है । उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कुछ और नहीं बल्कि संविधान बदनाम यात्रा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के संविधान को अलोकतांत्रिक और छलपूर्ण तरीके से डराने-धमकाने की राहुल गांधी की जानबूझकर और बार-बार की गई कोशिशें बुरी तरह विफल होंगी। जब हमारे संविधान को बदनाम करने की बात आती है तो राहुल गांधी हमेशा से ही सनकी और अपमानजनक रहे हैं। इस यात्रा का असली कारण कांग्रेस और राजद की विफलता का डर है। वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी जो कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इस लिहाज से बिहार की जनता जानती है कि यह मुख्य रूप से राज्य में कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। यह यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी कर रहा है। भारत की जनता उन लोगों के साथ नहीं खड़ी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। बिहार की जनता जानती है कि चुनाव आयोग उन्हें कैसे न्याय देगा।

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर कई राउंड फायरिंग, बाल-बाल बचे परिजन, हमलावरों की तलाश जारी

नई दिल्ली । रविवार सुबह बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे सेक्टर 57 में हुई, जब बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनके घर पर 20 से 24 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए। जिस समय हमला हुआ, एल्विश यादव घर पर नहीं थे। वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। हालांकि, उनके परिवार के कुछ सदस्य और केयरटेकर घर के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। साथ ही, इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इस घटना के बाद, पुलिस

ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और परिवार की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की जांच की जाएगी। एल्विश यादव के पिता ने बताया कि इस घटना से पहले उन्हें किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावरों ने मोटरसाइकिल से आकर गोलीबारी की। उनमें से दो बाइक से उतरे और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जबकि एक बाइक पर ही बैठा रहा। 27 वर्षीय एल्विश यादव एक लोकप्रिय यूट्यूबर है, जिन्होंने 2023 में बिग बॉस ओटीटी 2 जीतकर काफी शोहरत हासिल की थी। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वे म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। हालांकि, एल्विश का नाम विवादों में भी रहा है। पिछले साल, उन्हें नोएडा पुलिस ने रव पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इस मामले में जांच अभी भी जारी है।

दिल्ली में वीभत्स वारदात! चरित्र पर सवाल उठाने के बाद बेटे ने ही किया मां का रेप, पिता से बोला- तलाक दे दो

नई दिल्ली ।

दिल्ली के हौज काजी इलाके से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. एक 39 वर्षीय एक शख्स ने अपनी ही मां के साथ कथित तौर पर रेप किया. यह घटना तब हुई जब महिला अपने पति और बेटी के साथ सऊदी अरब की तीर्थयात्रा करके लौटी थीं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ हौज काजी थाने पहुंचीं और बेटे पर मारपीट और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया. महिला ने बताया कि उनका बेटा लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा था और अक्सर मारपीट करता था. महिला ने पुलिस को बताया कि वह 25 जुलाई को अपने पति (72 वर्ष) और बेटी के साथ सऊदी अरब तीर्थयात्रा के लिए गई थीं. इस दौरान उनका बेटा बार-बार पिता को फोन करके मां पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता रहा. वह पिता पर दबाव डाल रहा था कि तुरंत दिल्ली लौटकर मां से तलाक ले लें. परिवार 1 अगस्त को दिल्ली लौटा. उसी दिन बेटे ने मां के साथ मारपीट की और अगले दिन फिर से हमला करने की कोशिश की. महिला डर के कारण कुछ दिन के लिए अपनी बड़ी बेटी के ससुराल में जाकर रहने लगीं, लेकिन हालात सुधरे नहीं.11 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे जब महिला घर लौटीं तो बेटा उनसे अकेले में बात करने पर अड़ा. फिर उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और चाकू व कैंची से धमकाया. इसी दौरान उसने कथित तौर पर अपनी मां का रेप किया. महिला ने पुलिस को बताया कि डर और शर्म के कारण उन्होंने यह बात तुरंत किसी को नहीं बताई. वह अपनी बेटी के साथ ही कमरे में सोने लगीं. लेकिन 14 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे बेटे ने फिर वही घिनौना काम किया. इसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाई और सीधे पुलिस थाने पहुंच गईं. दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ग्रेजुएट है लेकिन फिलहाल बेरोजगार है. वहीं पीड़िता अशिक्षित गृहिणी है और उनके पति सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है.

ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका, दिल्ली में अब हर महीने लगेगी लोक अदालत

नई दिल्ली।

राजधानी के सभी छह जिला न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े करीब 4.15 करोड़ से अधिक चालानों को निपटाने के लिए अब हर महीने लोक अदालत लगेगी। पहले लोक अदालत हर तीन माह में लगती थी। इसके अलावा चालान भुगतने के लिए अदालतों की संख्या भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बीते हफ्ते ही लोक अदालत लगाने और अदालतों की संख्या बढ़ाने की संस्तुति की है। अब आदेश के अनुपालन में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। राजधानी में 2019 से 2024 तक छह साल में लोक अदालतों और सालभर न्यायालयों के जरिये करीब 60 हजार लंबित चालान ही निपटाए जा सके। यानी हर साल करीब 10 हजार चालानों का निपटारा किया जा रहा था, जिससे न्यायालयों में चालानों का बोझ बढ़ता चला जा रहा था।

दिल्ली पहला राज्य बनेगा जहां हर माह लगेगी लोक अदालत

लंबित चालानों का निपटारा जल्द करने के लिए कदम उठाया गया है। यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी का कहना है कि जिस गति से हर साल केवल 10 हजार लंबित चालानों का निपटारा हो पा रहा था। उससे इनको समाप्त करने में न्यायालयों को 35 साल से अधिक का समय लग सकता था। न्यायालयों में चालानों के बढ़ते बोझ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने छह सदस्यीय कमेटी का गठन कर उन्हें सुझाव देने को कहा था। 18 मार्च को हाई कोर्ट द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति प्रतीक जालान को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), अतिरिक्त मुख्य सचिव व आयुक्त परिवहन विभाग, विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात, संयुक्त सचिव भारत सरकार प्रवीण कुमार राय, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव शामिल थे। कमेटी के सदस्यों ने हर मुद्दे पर गहन अध्ययन कर लंबित यातायात चालानों को कम करने और भविष्य में लंबित चालानों की संख्या को भी रोकने के लिए गहन अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप दी। जिसके बाद हर माह लोक अदालत लगाने व अदालतों की संख्या बढ़ाने आदि कई दिशा निर्देश दिए गए।

सात महीने में कटे 64 लाख चालान

उक्त निर्देश का पालन करने के लिए दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग और यातायात पुलिस तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। चालान भुगतने के लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं होने के कारण वाहन चालक धड़ल्ले से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान आने पर भुगतने में लापरवाही बरतते हैं। जिससे चालानों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस साल के चालान के आंकड़ों को देखें तो सात माह में विभिन्न तरह के ट्रैफिक उल्लंघन के आन स्पाट 33,02,644 चालान कटे, जिनमें 32,28,233 चालान लंबित हैं। उसी तरह कैमरों से 30,69,251 चालान कटे, जिनमें 30,00,429 चालान लंबित है।

वर्तमान स्थिति

छह जिला न्यायालयों में एक में भी यह सुविधा नहीं है जहां लोग सुबह से शाम तक चालान भुगत सकें। हर न्यायालय में केवल दो घंटे के लिए ईवनिंग कोर्ट चलता है। लोक अदालत में व्यावसायिक वाहनों के मालिक अधिकतम दो और आम लोग चार से पांच चालान भुगत सकते हैं।

दरगाह से ज़ायरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी

बरेली । उर्से रज़वी में शामिल होने देश-विदेश के लाखों ज़ायरीन बरेली पहुँच रहे है। उनकी मदद के लिए दरगाह की तरफ से 1500 वालिंटियर लगाए गए है। जो ज़ायरीन के ठहराने,खान-पान,दरगाह पर हाज़िरी,ट्रैफिक आदि में मदद करेंगे। दरगाह के सज्जादानशीन मुफ़्ती अह्सन रज़ा क़ादरी(अहसन मियां) ने ज़ायरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए है। किसी ज़ायरीन को कही कोई दिक़त आती है तो वो लोग इन नम्बर पर कॉल कर मदद मांग सकते है।

शाहिद नूरी 9219878651
अजमल नूरी 8077909456
परवेज़ नूरी 9259213602
नासिर कुरैशी 9897556434
औररंगज़ेब नूरी 9219722092
ताहिर अल्वी 9219725692
मंजूर रज़ा 9258545113
अब्दुल माजिद 9675315738
नासिर कुरैशी 9897556434.

कांग्रेस दफ्तर विवाद मामला: जांच कमेटी में 24 घंटे बाद ही बदलाव, अब आठ की जगह 11 सदस्यीय समिति बनाई गई

मुरादाबाद ।

मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के विवाद का हल निकालने के लिए गठित जांच कमेटी में एक दिन बाद ही बदलाव कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस ने अजय सारस्वत सोनी की जगह दो नए कन्वीनर (समन्वयक) बना दिए हैं।

अब सूची 11 सदस्यीय हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के गुरहट्टी स्थित कार्यालय को लेकर चल रहा विवाद अब और गंभीर हो गया है। कार्यालय की पिछले दिनों बची हुई छत भी ढहा दी गई। साथ ही जीने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस और भूमाफिया की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। इस मामले में जिलाध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आठ

सदस्यों की एक समिति बनाकर तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। इस समिति में मौजूदा जिला व महानगर अध्यक्षों को ही शामिल किया गया था। पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सारस्वत सोनी को इसमें समन्वयक नियुक्त किया गया था लेकिन 24 घंटे में सूची संशोधित कर दी गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी और बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंदमोहन गुप्ता को भी इसमें शामिल किया गया है। पार्टी के प्रवक्ता सुधीर पाठक के अनुसार इस बार एआईसीसी सचिव और संपत्ति मामलों के जानकार नीलेश पटेल लाला को समन्वयक बनाकर गुजरात से दोबारा यहां भेजा जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद दानिश अली को भी दूसरे समन्वयक के रूप में नामित किया गया है।

दानिश अली ने मामले की जमीनी पड़ताल भी शुरू करते हुए सभी सदस्यों को कागजों के साथ आने का बुलावा भी भेज दिया है ताकि कानूनी लड़ाई के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। नई सूची में नीलेश पटेल और दानिश अली के अलावा सदस्य के रूप में अजय सारस्वत सोनी, विनोद गुंबर, जुनैद कुरैशी, फूल कुंवर, अनुभव मलहोत्रा, असलम खुर्शीद, असद मौलाई, देश राज शर्मा और आनंद मोहन गुप्ता शामिल हैं।

छत के रास्ते घूसे चोरो ने उड़ा दिये पांच लाख से अधिक के गहने

पडरौना, कुशीनगर।

-रविंद्र नगर थाना के गांव परसादपुर में दिल दहला देने वाली घटना
- शातिर चोरों ने घर में ही सो रहे परिजनों को लगने नहीं दिया भनक

गांवों में चोरी की घटनाओं की भरमार सी आ गयी है। जिससे ग्रामीण दहशतजता हैं। ताजा मामला जनपद मुख्यालय स्थित रविन्द्र नगर थाना क्षेत्र के परसादपुर गांव का है। यहां के निवासी नर्वदेश्वर सिंह के घर में छत के रास्ते घुसे शातिर चोरों ने बेटी व मां के पांच लाख से अधिक के सोने व चांदी के गहने ले उड़े।

सुबह चार बजे जगे परिजनों को इस वारदात की जानकारी होने पर सभी के होश उड़ गये। रविंद्र नगर थाना पुलिस को दिये तहरीर में परसादपुर गांव निवासी नर्वदेश्वर सिंह पुत्र परमानंद सिंह ने लिखा है कि 13 अगस्त की रात में परिवार के सभी पुरूष व महिला सदस्य भोजन करने के बाद सो गये। 14 अगस्त की सुबह 4 बजे जगने के बाद कमरों में रखे बाक्स व आलमारी में रखे सामान बिखरे दिखे तो किसी अनहोनी की आशंका हुई। छानबीन करने पर पता चला कि शातिर चोरों ने मकान के पीछे खड़े पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर छत से नीचे घर में उतरकर बड़ी घटना को अंजाम दिया है।

परिजनों ने जब आभूषणों की जांच परख की तो पता चला कि बड़गांव अपने ससुराल से मायके परसादपुर आयी बेटी का सोने का सिकड़, सोने का कंठमाला, अंगुठी, कान का झाला, पायल तथा पत्नी का सोने का मंगल सूत्र, सिकड़, अंगूठी आदि सामान गायब हैं। चोरों ने इतने शातिराना अंदाज से घटना को अंजाम दिया कि घर में ही सो रहे परिजनों को इसकी भनक तक नही लगी। चोर जिस रास्ते घर में घुसे थे उसी रास्ते आभूषण लेकर चंपत हो गये। पीड़ित ने तहरीर में लिखा है कि चोरी की घटना की तहरीर मुकामी पुलिस को दे दिया हूं, लेकिन अभी तक पुलिस ने न तो कोई मुकदमा ही दर्ज किया न ही चोरों को पकड़ने के लिए कोई सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। पीड़ित ने मामले की जांच कर शातिर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने और घर से चोरी गये पांच लाख से अधिक के गहनों के बरामदगी की मांग की है।

इमाम हुसैन के चेहलुम पर निकला जुलूस, हुई मजलिस-ए-अज़ा

मुरादाबाद। महानगर के आजाद नगर स्थित इमाम बारगाह मोहम्मदिया हाल में इमाम-ए-मेहंदी यूथ मिशन की ओर से रविवार को हजरत इमाम हुसैन के चेहल्लुम के मौके पर मजलिस-ए-अज़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिशन के सेक्रेट्री वसी अब्बास नकवी और उनके साथियों ने मरसिया खूवानी पेश की। मजलिस की अध्यक्षता करते हुए मौलाना नाज हैदर ने कहा कि कर्बला की जंग हक और बातिल के बीच थी, जहां इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत की खातिर शहादत देकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि सच हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है। कर्बला के वाकिये ने हमें रिश्तों, दोस्ती और कुर्बानी की अहमियत समझाई। नमाज़-ए-जौहर के बाद इमामबारगाह मोहम्मदिया हाल से शबीह-ए-रौज़ा-ए-इमाम हुसैन और आलम मुबारक का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस कोहिनूर तिराहा, सुल्तान हॉस्पिटल और करुला होते हुए ज़ाहिद नगर से निकलने वाले जुलूस में शामिल होकर कर्बला पहुंचा। जुलूस में इमाम-ए-मेहदी यूथ मिशन के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में अजादार शामिल हुए। इस दौरान कलाम हसनैन, रग़िब अली, जैनुल काज़मी, डॉ. कायम रज़ा, वसी अब्बास नकवी, ताहिर, जिया, शबाब, अमीर, हुसैन अब्बास, पप्पू भाई, आमिर खान, शकील पाशा, काज़िम, कमर अब्बास बाक़री, मख़दूम अंसारी, हैदर, काशिफ, नाज़िश, अन्वर, सलीम, मोहम्मद अब्बास, राजू, जावेद, अनीस हैदर, सलमान बक़री, डॉ. कायम राजा, अली वाहिद, इमदाद, खुशनुद अनवर, शबाब नक़वी, इक़बाल हसन, मोहम्मद दानिश, फिरासत हुसैन, मुन्नू और शोएब नकवी शामिल रहे।

सपा सांसद रुचि वीरा का पूर्व सांसद पर तंज, विरोध करने वालों को बताया 'जयचंद'

मुरादाबाद। सपा सांसद के बयान से पार्टी की अंदरूनी कलह एक बार फिर सतह पर आ गई है। पार्टी की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के पूर्व सांसद का नाम लिए बिना तीखा हमला किया है। उन्होंने उन्हें पार्टी का जयचंद करार दिया और सपा मुखिया अखिलेश यादव से मांग की कि ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर अपने कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जब अखिलेश यादव द्वारा पार्टी की विधायक पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने पर निष्कासित करने का सवाल आया तो सांसद ने प्रतिक्रिया में कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और खुले तौर पर उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। विरोध करने वाले पार्टी में जयचंद का काम कर रहे हैं। सांसद ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कुछ लोगों ने खुलेआम विरोध किया था और उनके वीडियो वायरल हुए थे, इसके बावजूद वे आज भी पार्टी में बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 में सरकार बनाना है। अगर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई नहीं होगी तो यह पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करेगी। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जिसे हाईकमान तय करे, उसके लिए सभी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए।

उत्तराखंड से यूपी आने वाले मुर्गे और अंडे की सप्लाई पर रोक, बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर फैसला

मुरादाबाद।

रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील क्षेत्र के सिरोहा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू (एच-5 एन-1) की पुष्टि के बाद मुरादाबाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शासन ने एहतियातन उत्तराखंड से आने वाले मुर्गे और अंडे की सप्लाई के आवागमन पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर जिले के रिटेल बाजार पर दिखाई देने लगा है। एक ओर अंडों की बिक्री में कमी आई है तो दूसरी ओर कीमतों में एक रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। शासन की रोक और प्रशासनिक सतर्कता से दहशत का माहौल है। उपभोक्ता जहां चिकन और अंडे खरीदने से बच रहे हैं, वहीं विक्रेता भी सप्लाई रुकने से परेशान हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आश्वस्त किया है कि सावधानी और सतर्कता से बर्ड फ्लू का खतरा टाला जा सकता है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पशुपालन, स्वास्थ्य, पंचायती राज और वन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कुक्कुट पक्षियों की

अस्वाभाविक बीमारी या मृत्यु होती है तो उसकी तत्काल सूचना दी जाए। सैंपल समय रहते नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, भोपाल या आइवीआरआइ, इज्जतनगर (बरेली) में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। वन विभाग को भी अपने क्षेत्र में पक्षियों की आकस्मिक मौत पर नजर रखने को कहा गया है। शहर के आसपास की झीलों की निगरानी कराई जा रही है। पोल्ट्री फार्म संचालकों और रिटेल में मुर्गे का मांस बेचने वालों को गाइड लाइन का पालन करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. सुनील दत्त ने बताया कि रामपुर में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद से अब तक 135 नमूने जांच के लिए आइवीआरआइ (इज्जतनगर) बरेली भेजे गए हैं। इससे पहले 95 नमूने भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। नए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी हालांकि बर्ड फ्लू का मामला रामपुर में सामने आने के बाद जिले में एहतियात और सतर्कता की स्थिति और कड़ी कर दी गई है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ठाकुरद्वारा को आवश्यक सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा कर त्वरित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

बाजार पर भी पड़ रहा असर

बर्ड फ्लू की आशंका का असर सीधे तौर पर अंडे और चिकन बाजार पर पड़ा है। अंडा विक्रेता श्याम सुंदर ने बताया कि बाहर से सप्लाई बंद हो गई है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। पहले सात रुपये में मिलने वाला अंडा अब आठ रुपये तक बिक रहा है। वहीं चिकन की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है क्योंकि जिले में इतनी बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म नहीं हैं कि स्थानीय मांग पूरी हो सके। इसलिए बाहर से आने वाला अंडा और मुर्गा ही मांग पूरी करता है।

इन नंबरों पर करें फोन

जिलाधिकारी ने साफ किया कि संदिग्ध मामलों में पीपीई किट का प्रयोग अनिवार्य है और संक्रमित स्थलों पर आमजन का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं भी पक्षियों की असामान्य मौत या बीमारी का मामला दिखे तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद (मो. 8765957907) या उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ठाकुरद्वारा (मो. 8802163550) को दें।